ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 127-130

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

समाज एवं नयी शिक्षा नीति का समन्वित मूल्यांकन

डॉ0 सुशील कुमार सिंह

सहायक प्रोफेसर– समाजशास्त्र विभाग, स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 17.02. 2022, Revised- 22.02 2022, Accepted - 27.02.2022 E-mail: aaryavrat2013@gmail.com

सारांशः – *भारतीय समाज सदैव से ही एक पारंपरिक समाज रहा है। यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता अत्यन्त ही प्राचीन है। प्राचीन काल से ही भारतीय परम्परा एवं संस्कृति को बनाये रखने एवं इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हस्तान्तरण में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस प्रकार सभ्यता की शुरुआत से ही शिक्षा भारतीय समाज की बुनियाद रही है। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुल आधारित शिक्षा प्रणाली पायी जाती थी जहाँ पर पारंपरिक तथा प्रकृति के वातावरण में रहकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार इस प्रणाली में समाज से संवाद तथा ज्ञान एवं इसके उपयोग के बीच सम्बन्ध की ज्यादा संभावना थी। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में संचालित हमारी शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप ही है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली पूर्णतया औपचारिक थी और इस प्रणाली ने शिक्षा के विकास में बहुत योगदान किया। हमारे देश की सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में निरंतर व्यापक सुधार एवं परिवर्तन किये जाते रहे हैं। नयी शिक्षा नीति 2020 भारत में महत्वपूर्ण सुधारों के तहत शामिल किया गया है। इस नयी शिक्षा नीति ने भारत में व्यापक सामुदायिक समन्वय स्थापित किया है। इस नीति के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों के लिए जनआधारित शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की है।*

कुंजीभूत शब्द– पारंपरिक समाज, संस्कृति एवं सभ्यता, भारतीय परम्परा, हस्तान्तरण, सभ्यता, भारतीय समाज, बुनियाद।

एक गतिशील समाज के लिए शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में प्रचलित शिक्षा नीतियों में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच समानता पर बल दिया गया है। शिक्षा को समाज से जोड़ने के लिए सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह अहम है कि समुदाय अपने स्वामित्व का शैक्षिक प्रयासों तक विस्तार करे। दूसरी तरफ यह भी आवश्यक है कि शैक्षिक संस्थान अपने कार्यक्रमों और सेवाओं को समाज के सशक्तीकरण में लगाये। इसके द्वारा शिक्षा एवं समाज के बीच अन्तर–सम्बन्ध विकसित होगा।

नयी शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है, कि शिक्षा को पूर्ण रूप से समुदाय के अनुरूप आधारित एवं समन्वित किया जाना चाहिए। इसी के परिणामस्वरूप ही शिक्षा में मौलिक सुधार सम्भव हो सकेगा। साथ ही यह शिक्षा समाज के लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हो सकेगी। शिक्षा में लचीलापन संस्थागत स्तर पर सामुदायिक भागीदारी का अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वायत्तता के कारण शैक्षिक संस्थाओं को मजबूती एवं ताकत मिलती है। लचीले एवं स्वायत्त संस्थान समाज के साथ अन्तरसम्बन्ध के लिए कार्यक्रमों को डिजाइन और विकसित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सभी पहलू हमें यह एहसास कराते हैं कि शिक्षा सामाजिक न्याय और परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने का साधन है। इस नीति में शिक्षा में समाज की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है। समाज की प्रत्यक्ष भूमिकाओं में ऑगनबाड़ियों को शिक्षा के दायरे में लाना, विभिन्न स्तरों पर कौशलों को जोड़ना, शिक्षा को सम्पूर्ण ओर बहुविषयक बनाना तथा अनुभव के जरिए ज्ञानार्जन की ओर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है। इस नीति में यह भी ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार शिक्षा के मुख्य पाठ्यक्रम से स्थानीय कौशलों को जोड़ने तथा समुदाय को प्रभावित करने वाले अनुसंधान पर जोर दिया गया है।

भारत में प्रचलित विभिन्न शिक्षा नीतियों के माध्यम से शिक्षा को समाज के कल्याण हेतु उपयोगी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किया जाता रहा है। नयी शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने पर जोर दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा पर इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। बुनियादी अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में बच्चों की पढ़ने की क्षमता और अर्थ या भाव समझने की क्षमता और वास्तविक जीवन के विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस प्रकार प्रारम्भ से ही हर बच्चों को निपुण तथा मानसिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी के लिए तथा समानता पर आधारित और समावेशी शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के उद्देश्य से नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा तक सबकी पहुँच, सभी की भागीदारी एवं शिक्षण स्तर के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार इस नीति में समानता को ही समावेशी व्यवस्था का आधार माना गया है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास पर भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

समाज के साथ समन्वय स्थापित करने में भी नयी शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इस नीति में सबके लिए गुणवत्तापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँच, भागीदारी और ज्ञानार्जन के परिणामों में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतर को दूर करने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये हैं। न्यायसंगतता को समावेशी विचार मानते हुए और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस नीति में राज्यों के बीच विशाल अन्तर को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया गया गया है। इसमें कमजोर समूहों की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र–स्पेशल एजुकेशन जोन ;र्द्ध घोषित करने की सिफारिश की गयी है जिनमें नीतियों और योजनाओं को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू किया जायेगा। इस नीति में सभी ई तक पहुँच, भागीदारी और ज्ञानार्जन परिणाम की समस्याओं तथा स्कूली और उच्चतर शिक्षा में समूहों और क्षेत्रों के बीच विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को दूर करने के लिए समुचित रणनीतियाँ अपनाने का सुझाव दिया गया है। शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक ज्ञानार्जन के परिणामों में न्यायसंगतता को बढ़ावा देना नयी शिक्षा नीति–2020 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक प्रमुख लक्ष्य है।

शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी– शिक्षा समाज के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का होना आवश्यक है। नयी शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत एक ऐसी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गयी है जिसमें लोककल्याणकारी निजी एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। समुदाय आधारित शिक्षा ही सही मायने में एक सार्थक शिक्षा साबित हो सकती है। स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए भी सामुदायिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्थानीय समुदाय अथवा समाज सक्रिय हो और स्कूलों की गतिविधियों में हिस्सा ले तभी गाँव के विद्यालय प्रभावी ढंग से काम करते हैं। अभिभावकों की सक्रियता इस शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सफल बना सकती है। इस प्रकार इस नीति के अन्तर्गत आंगनबाड़ियों को पूरी तरह से समेकित परिसर या समूहों के रूप में संचालित किये जाने का लक्ष्य है। इसके तहत बच्चें के अभिभावकों और शिक्षकों को स्कूल परिसर के कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जायेगा। अब आंगनबाड़ियों को भी शिक्षा से जोड़े जाने के कारण उनके दायरे का भी विस्तार सम्भव हो सकेगा।

इस प्रकार नयी शिक्षा नीति के कारण समूह स्कूलों की अवधारणा से विद्यालय के निर्माण और शिक्षा बढ़ाने समुदाय अथवा समाज की भूमिका निर्धारित होती है। स्कूल परिसर एवं उसके आस–पास के विद्यालयों को एक समूह में एकत्र करने की स्थिति भी उत्पन्न हो पाती है। इसके कारण स्वयं ही समाज एक संगठित रूप से सामुदायिक ढाँचे का निर्माण करता है। आस–पास एक सामूहिक भावना की स्थिति उत्पन्न होने के कारण शिक्षा के लिए शिक्षकों द्वारा ज्ञान एवं भौतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से साझा कर सकते हैं। इसका सर्वाधिक लाभ आस–पास के समुदायों को पूर्ण रूप से मिल सकेगा। साथ ही विस्तृत आधार वाले स्कूल परिसरों और समूहों से स्थान और स्थिति के अनुरूप नवोन्मेषों को बढ़ावा भी मिल सकेगा।

कभी–कभी स्कूल के प्रबंधन एवं संचालन में स्थानीय समितियाँ भी मददगार साबित हो सकती है। स्थानीय समूहों की सहायता के द्वारा ही सम्पूर्ण विद्यालय परिसर तथा शैक्षिक माहौल को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ–साथ शिक्षा की समाज के प्रति भूमिका भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। गैर–सरकार संगठनों को स्कूल बनाने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। स्कूलों के प्रबंधन और विकास में सामुदायिक भागीदारी हो तो वे नतीजों को हासिल करने के लिए ज्यादा सक्रिय होते हैं। स्कूलों के विकास में सामुदायिक अथवा समाज की भागीदारी की संशोधनों, प्रक्रियाओं एवं परिणामों के लिहाज से विद्यालय के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नयी शिक्षा नीति में ज्ञानार्जन को ज्यादा प्रभावी बनाने तथा बुनियादी साक्षरता और ज्ञान के लक्ष्यों को हासिल करने में समुदाय, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवियों की भागीदारी का सुझाव दिया गया है। इस प्रकार नयी शिक्षा नीति 2020 में स्कूलों की अप्रयुक्त अवसंरचना क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए सामाजिक चेतना केन्द्र खोलने का सुझाव दिया गया है। ये केन्द्र समाज के लिए सामाजिक, बौद्धिक और स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार शिक्षण एवं शिक्षा के बाद के समय में होने वाली इन गतिविधियों से सामाजिक एकजुटता एवं सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य–

1. समाज एवं शिक्षा के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों को ज्ञात करना एवं दोनों के मध्य एक समन्वय स्थापित करना जिसके कारण शिक्षा का पूर्ण मूल्यांकन भी किया जा सके।
2. शिक्षा की गुणवत्ता एवं आवश्यकता को समाज के अनुरूप इस प्रकार तालमेल स्थापित करना जिससे समाज अथवा समुदाय को उचित तथा सर्वोपरि स्थान दिया जा सके।
3. नयी शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत सुझावों एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत समाज एवं शिक्षा के मध्य एक पारस्परिक समन्वय

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

अथवा सामंजस्य की स्थापना करना।

4. शिक्षा नीति के व्यापक रूप से लागू एवं क्रियान्वयन के पश्चात समाज में पड़ने वाले शिक्षा के व्यापक प्रभावों का भी पूर्ण मूल्यांकन करना अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

5. शिक्षा को समाज के लिए उसके अनुरूप निर्मित किया जाता है, नयी शिक्षा नीति 2020 क्या समाज के अथवा समुदाय के साथ पूर्ण रूप से समन्वित हो पायी है अथवा उसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। इसका भी ऑकलन करना।

6. समुदाय में नयी शिक्षा नीति एवं अन्य शिक्षा नीतियों के परिणामस्वरूप कितने महत्वपूर्ण बदलाव हुए तथा नई शिक्षा नीति के व्यापक सुधारों का भी आकलन तथा विश्लेषण करना।

7. शिक्षा सभी वर्गों, समुदायों एवं समाजों के अनुरूप संचालित की जानी चाहिए जिससे शिक्षा को समाज के कल्याणकारी कार्यक्रमों के रूप में ही संचालित किया जा सके। इस प्रकार इस नीति में शिक्षा के सामाजिक महत्व की भूमिका का मूल्यांकन एवं परीक्षण करना।

इस प्रकार नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों एवं प्रयोजनों को हासिल करने के लिए व्यवस्था का परिवर्तनकारी एजेंडा निर्धारित किया गया है। स्कूली शिक्षा के प्रमुख सुधारों में स्कूल परिसरों/समूहों की स्थापना, स्कूल मापदण्डों और प्राधिकारणों का निर्धारण तथा विद्यालय परीक्षा बोर्डों में सुधार शामिल हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की सिफारिश की गयी है। यह आयोग उच्चतर शिक्षा में एक मात्र नियामक संस्था होगा। इसके अलावा माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण तथा उपयोगी बनाने का सार्थक प्रयास किया गया है। इस प्रकार की संस्था गठन के द्वारा भी शिक्षा की महत्वपूर्ण कमियों को सुधारा जा सकता है। शिक्षा की प्रमुख समस्याओं के सुधार के द्वारा ही इसे समाज के लिए उपयोगी एवं सार्थक बनाया जा सकता है। हमारे अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को समाजोपयोगी एवं शिक्षा का समुदाय एवं समाज के साथ सामाजिक समन्वय की स्थापना करना भी है।

नयी शिक्षा नीति एवं सामाजिक समन्वय प्रणाली– नयी शिक्षा नीति की एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण सिफारिश शिक्षा को विस्तृत एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर पूर्ण विकसित करने की है। इस दिशा में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक सुधार एवं बदलाव की सिफारिश की गयी है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बहुविषयक संस्थान में तब्दील हो जायेंगे। वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षण अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी के साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित करेंगे। बहु विषयक दृष्टिकोण से उनके लचीले एवं नवोन्मेषी पाठ्यक्रम समाज की जरूरतों से जुड़ेंगे। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली पाठ्यक्रमों के विविधतापूर्ण सम्मिश्रण को जन्म देती। ज्ञानार्जन के आधार पर शिक्षा को सफल एवं विस्तृत बनाने के लिए सामुदायिक सेवा, पर्यावरण और मूल्य आधारित शिक्षा जैसे क्षेत्रों से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा जलवायु प्रबन्धन, स्वच्छता, जैव विविधता, संरक्षण, जैविक संसाधन एवं जैव विविधता प्रबन्धन, वन और वन्य जीव संरक्षण तथा संवहनीय विकास और जीवन शैली जैसे क्षेत्रों में भी परियोजनाओं का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। मूल्य आधारित शिक्षा में मानवीयता, नैतिकता, संवैधानिकता और वैश्विक मानक मूल्यों तथा जीवन कौशल का विकास शामिल है। इस प्रकार इसमें सामाजिक सेवा, सामुदायिक कार्यक्रमों में भागीदारी को भी शामिल किया गया है। छात्रों को स्थानीय उद्योगों, व्यवसायों, कलाकारों एवं शिल्पकारों के साथ प्रशिक्षण के अवसर मुहैया कराया जायेगा। साथ ही उच्चतर शिक्षा के साथ अनुसंधान का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके परिणामस्वरूप ही छात्रों में समाज तथा सामुदायिक जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। छात्रों में खेल, संस्कृति, पर्यावरण, क्लबों और समुदायिक सेवा परियोजनाओं के जरिये अपने ज्ञान के व्यावहारिक पक्ष से सक्रियता से जुड़ सकेंगे। इस तरह यह देखा जा रहा है कि निश्चित रूप से यह नयी शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाती है जिसके कारण वे दुनिया के मुद्दों को समझते हुए ज्यादा शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी एवं संवहनीय समाजों को सक्रियता से बढ़ावा देने वाले बन सके। साथ ही साथ वे एक संगठित समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

मूल्यांकन एवं निष्कर्ष– शिक्षा का उद्देश्य समाज को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने की दिशा में कार्यरत रहना होता है। शिक्षा में ज्ञानार्जन, अनुसंधान एवं विकास के लिए सामुदायिक भागीदारी का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस नीति में यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक हे और इसे बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों एवं संस्थानों द्वारा क्या कार्य किया जाना चाहिए। इस नीति में सामाजिक शिक्षा के स्पष्ट उद्देश्य तथा कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं। विद्यालयों एवं संस्थानों के सामने अब इसे सक्रियता से लागू करने की महत्वपूर्ण चुनौती है। सामुदायिक भागीदारी को संस्थानों की दृष्टि, उद्देश्य, लक्ष्यों और योजनाओं में शामिल कर इसे संस्थागत रूप दिये जाने की जरूरत है। सामुदायिक भागीदारी को शिक्षण, ज्ञानार्जन और अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों के साथ जोड़ने के लिए संस्थागत प्रणालियों को पूर्ण विकसित करना होगा।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

शिक्षा में सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के पास कुछ विकल्प है जिनमें पहला, वे सरकार से मिलने वाले दिशा निर्देशों को लागू करें। दूसरा, सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं से दिशा नहीं मिलने की स्थिति में भी वे नीति भावना के अनुरूप उसे लागू करे। वे सम्पूर्ण सामुदायिक भावना को ग्रहण करते हुए उस दिशा में कार्य करें। एक अन्य विकल्प है, यह है कि वे नयी शिक्षा नीति 2020 से भी आगे जाकर समुदाय को हित प्रदान करते हुए। अपने दिशा–निर्देशों को लागू करें। संस्थानों को अपने हितधारकों को यह बताना होगा कि वे समाज का हिस्सा है। इसीलिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समाज को संस्थान के नजदीक लाना होगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामाजिक सम्पर्क की जरूरत को शिक्षा के जरिए पूर्ण करने की कोशिश की गयी है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में सरकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज के सम्पूर्ण सहयोग के द्वारा ही हम इस नयी शिक्षा को पूर्ण सफल तथा समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं।

समुदाय के लिए महत्वपूर्ण नयी शिक्षा नीति–2020 में ज्ञानार्जन के तार्किक लक्ष्य को भी स्पष्ट किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान हासिल करना ही नहीं होना चाहिए बल्कि इसका लक्ष्य का एक ऐसा परिवेश बनाना होना चाहिए जिसमें सिद्धान्तों का उपयोग हो और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इनके व्यावहारिक इस्तेमाल को समझा जा सके। इस तरह सामाजिक परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में देखा जाय तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य समाज और शिक्षा के बीच खाई को दूर करना है। शिक्षा को सदैव ही समाज का हिस्सा होना चाहिए तथा इसे समाज के हित में ही कार्य करना चाहिए। समाज को सहक्रियात्मक संबंध के रूप में कार्य करने के लिए शैक्षिक संस्थानों के योगदान की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह सम्बन्ध तभी मजबूत एवं सफल हो सकता है जब सभी संस्थान अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण समझते हुए सामुदायिक भागीदारी को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करें। इस प्रकार यह नीति भारत के लिए तथा भारतीय समाज को संगठित करने में भी महत्वपूर्ण तथा मददगार सिद्ध हुई है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. होल्ट, जे0, 1990. लर्निंग ऑल द टाइम्स, डॉ0 कैपो लाइफलॉग्स बुक (फर्स्ट पब्लिस्ड, 1989).
2. घोष, एस0 एण्ड डे एस, 2000. ''पब्लिक एण्ड प्राइवेट? डिटरमिनेन्ट्स ऑफ पैरेन्टस पास्कूल चॉइस इन इण्डिया''.
3. राष्ट्रीय शिक्ष नीति (NEP), 2020, पृ0 10.
4. एनईपी, 2020, पृ0 6.
5. एनईपी, 2020, पृ0 2–25.
6. एनईपी, 2020, पृ0 152.
7. एनईपी, 2020, पृ0 129.
8. एनईपी, 2020, पृ0 39.
9. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय रिपोर्ट, 2020, नयी दिल्ली।
10. शिक्षा मन्त्रालय रिपोर्ट, भारत सरकार, 2021. पैरेन्टस इन्वाल्वमेन्ट इन चिल्ड्रन्स लर्निंग, दिसम्बर।
11. आहूजा, राम, 2010. सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
12. आप्टे, प्रभा, 1996. भारतीय समाज, क्लासिक पब्लिसिंग हाउस, जयपुर.
13. सिंह, डॉ0 बी0 एन0 जनमेजय सिंह, 2007. ग्रामीण समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. देसाई, ए0 आर0, 1997. भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

*****